

FY18 का बकाया चुकाने के निर्देश



गन्ना किसानों के बकाए में UP की 5 मिलों की आधी हिस्सेदारी

[माधवी शैली | नई दिल्ली]

उत्तर प्रदेश में बजाज हिंदुस्तान शुगर, सिंभावली शुगर, मवाना शुगर, मोदी शुगर और राणा शुगर पर गन्ना किसानों का काफी पैसा बकाया है। यह जानकारी खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने दी है। सरकार ने मिलों से किसानों का 2017-18 का बकाया चुकाने को कहा है। इसके साथ जल्द से जल्द 2015-16 और 2016-17 के पेंडिंग अकाउंट को भी क्लीयर करने को कहा गया है, जो 19,246 करोड़ रुपये के करीब है। मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी बताया कि वे चीनी मिलों को किसी तरह की सब्सिडी देने या शुगर बफर स्टॉक क्रिएट करने के बारे में नहीं सोच रहे।

गन्ना किसानों के बकाए पर इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) का कहना है कि सरकार को चीनी मिलों की मदद करने के लिए 2015-16 सीजन की तरह इस बार एफआरपी के हिस्से के तौर पर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सब्सिडी देने चाहिए। गन्ना किसानों की मौजूदा साल में उस सीजन की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिति खराब है।

मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकारों की तरफ से तय किए गए एसएपी के मुताबिक सितंबर 2016 को समाप्त हुए फसल वर्ष में गन्ना किसानों को 697 करोड़ रुपये और 2016-17 के लिए 545 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर 2017 में शुरू हुए मौजूदा सीजन के लिए 12 अप्रैल तक बकाया रकम 18,004 करोड़ रुपये थी। वहीं, केंद्र सरकार के एफआरपी के मुताबिक इसी अवधि में बकाया रकम 12,617 करोड़ रुपये थी। इस्मा ने मंगलवार को बताया कि 15 अप्रैल तक चीनी का उत्पादन 30 सितंबर के पूरे सीजन की मांग के मुकाबले 50 लाख टन अधिक था।

वहीं, खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'गन्ने का सबसे ज्यादा बकाया उत्तर प्रदेश (8,869 करोड़ रुपये), कर्नाटक (2,420 करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (2,213 करोड़ रुपये) में है। उत्तर प्रदेश में पांच मिलों पर करीब आधी देनदारी है।' अधिकारी ने बताया कि बजाज हिंदुस्तान के पास 15 चीनी मिलें हैं। इस कंपनी पर गन्ना किसानों का 2,709 करोड़ रुपये बकाया है। मोदी शुगर के पास दो यूनिट्स हैं और उस पर 514 करोड़ रुपये का बकाया है।

वहीं, मवाना पर 436 करोड़, सिंभावली शुगर पर 383 करोड़ और राणा पर 364 करोड़ रुपये का बकाया है। एसोसिएशन ने कहा कि ऊंचे स्टॉक की वजह से देशभर में चीनी का मार्केट प्राइस उत्पादन लागत से लगभग 8 रुपये प्रति किलो कम था।

Economic Times

(Hindi)

18-4-18

✓ R